आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
गुरूवार 12.12.2024
समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले में युवा नवोन्मेषकों से कहा– उनके समाधान भारत के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण।
- देहरादून में आज से विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आयुर्वेद एक्सपो शुरू हो रहा है।
- राज्य मंत्रिमण्डल ने प्रदेश की नई आवास नीति को मंजूरी दी, आवास निर्माण की पात्रता में कमजोर आय वर्ग की वार्षिक आय सीमा को तीन लाख से बढ़ाकर पांच लाख किया।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में निर्माण कार्यों के लिए तीन करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति दी।

स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश बडे पैमाने पर डिजिटल रूप से जुड रहा है इसके साथ ही साइबर अपराध भी लगातार बढ रहे हैं। श्री मोदी ने कल शाम स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले में वीडियों कांफ्रेंस के जरिए युवा नवोन्मेषकों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व में अग्रणी डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।श्री मोदी ने कहा कि भारत तेज गति से तभी आगे बढ सकता है जब सभी के प्रयास शामिल हों। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब देश नई चुनौतियों का सामना कर रहा होता है तो नवाचार से जुडे युवा आसाधारण समाधान प्रस्तुत करते हैं। नवोन्मेषकों के योगदान की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा इन लोगों ने हमें कभी निराश नहीं किया ब्लकि हमेशा मनोबल बढाया है।

विश्व आयुर्वेद कांग्रेस

राजधानी देहरादून में आज से विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आयुर्वेद एक्सपो की शुरुआत हो रही है। परेड मैदान में आयोजित यह कार्यक्रम आयुर्वेद के क्षेत्र में शोध, विकास और नई खोजों के लिए एक उत्कृष्ट मंच प्रदान करेगा।

इस बार का आयोजन ''डिजिटल स्वास्थ्य, आयुर्वेदिक दृष्टिकोण'' विषय पर आधारित है, जो आयुर्वेद को नई तकनीकों से जोड़ने पर जोर देगा। इस चार दिवसीय आयोजन में साढे पांच हजार से अधिक भारतीय और तीन सौ पचास से अधिक विदेशी प्रतिनिधि भाग लेंगे, जो आयुर्वेद और स्वास्थ्य से संबंधित नवीनतम तकनीकों और शोध पर चर्चा करेंगे। इस दौरान, विशेष रूप से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी और ब्लॉकचेन जैसी नई तकनीकों को आयुर्वेद के साथ एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित किया

जाएगा। इसके अलावा, आयुर्वेद एक्सपो में 350 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे, जो लाखों दर्शकों को आकर्षित करेंगे। इस प्रदर्शनी में भारत और विदेशों के प्रमुख आयुर्वेदिक संस्थान अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस आयोजन को आयुष मंत्रालय, उत्तराखंड सरकार और अन्य सहयोगी राज्यों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय आयुर्वेदिक उत्पादों को प्रमुखता देने का आह्वान किया है।

यातायात प्लान

12 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आयोजित विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के मद्देनजर देहरादून में परेड ग्राउंड के आसपास यातायात और पार्किंग व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए विशेष डायवर्ट प्लान लागू किया गया है। सम्मेलन के दौरान परेड ग्राउंड के चारों ओर सभी प्रकार के वाहनों, ठेलियों और रेहड़ियों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। सम्मेलन स्थल के आसपास जीरो–जोन रहेगा। वीआईपी और अधिकारियों के वाहन ईसी रोड, सर्वे चौक, रोजगार तिराहा से कान्वेंट तिराहे की ओर जाते हुए वीवीआईपी द्वार से प्रवेश करेंगे। कार्यक्रम में भाग लेने वाले नागरिकों को उनके वाहन निर्धारित ड्रॉपिंग प्वाइंट्स पर छोड़ने होंगे। आयुष सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों के वाहन रेंजर्स ग्राउंड, मंगला देवी इंटर कॉलेज, काबुल हाउस और दून क्लब के पास पार्क होंगे।

कैबिनेट

राज्य मंत्रिमण्डल ने प्रदेश की नई आवास नीति को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सरकार ने कमजोर आय वर्ग को आवास उपलब्ध कराने के दृष्टिगत लाभार्थी की वार्षिक आय सीमा को तीन लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया है। पहली बार निम्न और निम्न मध्यम वर्ग के साथ ही सामान्य वर्ग के लिए भी वार्षिक आय सीमा निर्धारित की गई है। आवास नीति में पहली बार पर्वतीय क्षेत्र बाखली शैली की आवासीय परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। बाखली शैली की आवासीय परियोजना में लाभार्थियों को पांच लाख 25 हजार रुपए तक का अनुदान मिलेगा, जबकि अन्य आवासीय परियोजनाओं में केंद्र व राज्य का यह अनुदान मिलाकर चार लाख रुपये होगा। यही नहीं, सरकार ने आवासीय परियोजनाओं के विकासकर्ताओं को भी भू उपयोग परिवर्तन समेत अन्य शुल्क में छूट दी है। सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य में उत्तराखंड ट्रांसजेंडर पर्सन्स कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है। इस बोर्ड के माध्यम से ट्रांसजेंडर के अधिकारों को सुरक्षित रखने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।

स्वीकृति

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न जिलों में निर्माण कार्यों के लिए तीन करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति दी है। इन योजनाओं में मंदिर सौंदर्यीकरण, मार्ग निर्माण, मेला स्थल विकास सहित विभिन्न कार्य शामिल हैं।

<u>जुर्माना</u>

बागेश्वर जिले की कपकोट तहसील में प्रशासन ने एक स्टोन क्रशर पर 70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना क्षमता से अधिक भंडारण करने पर लगाया गया है। इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेज दी गई है। क्षेत्र की उपजिलाधिकारी ने कहा है कि किसी भी क्रशर संचालक को मानक से अधिक भंडारण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

<u>समीक्षा</u>

चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने जिला विकास प्राधिकरण के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी संबंधित विभागों को परियोजनाओं के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने विशेष रूप से लंबित योजनाओं पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को परियोजनाओं में आ रही बाधाओं को प्राथमिकता से दूर करने को कहा। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण के तहत विकास कार्यों को गति देना बेहद जरूरी है ताकि जनता को सुविधाएं समय पर मिल सकें। बैठक में प्राधिकरण के राजस्व और व्यय, लंबित भवन स्वीकृतियों, अवैध निर्माणों पर कार्रवाई और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी योजनाओं का भी गहन विश्लेषण किया गया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं में पर्यावरणीय मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।

अब एक नज़र समाचार पत्र की सुर्खियों पर

राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव की ख़बर को राष्ट्रीय सहारा, दैनिक जागरण सहित लगभग सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से स्थान दिया है। हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखता है– अविश्वास प्रस्ताव पर राज्यसभा ठप, सत्ता पक्ष ने नोटिस को राजनीति से प्रेरित बताया। वहीं अमर उजाला का शीर्षक है अविश्वास प्रस्ताव पर संग्राम, सरकार बोली, विपक्ष ने सदन की गरिमा गिराई। नवोदय टाइम्स ने लिखा धनखड़ को हटाने के नोटिस पर रार, विपक्ष ने पक्षपाता होने का आरोप लगाया तो सत्तापक्ष ने राजनीति बताया।

राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक को भी सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता के साथ लिया है– नवोदय टाइम्स ने लिखा है– बिजली सब्सिडी को कैबिनेट की मंजूरी, दुरुपयोग पर देना होगा दोगुना जुर्माना। वहीं हिन्दस्तान समाचार पत्र लिखता है– उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेजों में इलाज सस्ता। अमर उजाला ने लिखा है– पांच लाख आय वालों को भी सस्ते घर, गरीबों के साथ मध्यम आय वर्ग को भी किफायती दरों पर आवास देगी सरकार।

रोड़वेज का बस बेड़ा बढेगा, यात्रियों को सुविधा। इस शीर्षक के साथ हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखता है– कैबिनेट ने 100 बीएस–सिक्स डीजल बसों की खरीद को दी मंजूरी।

पीआरडी कर्मियों को बेटियों की शादी के लिए मिलेंगे पचास हजार। इस ख़बर के साथ राष्ट्रीय सहारा लिखता है–पीआरडी स्थापना दिवस पर 14 बच्चों को एक लाख रुपए की धनराशि दी गई।

साइबर अपराध से जुड़ी देहरादून की एक ख़बर पर दैनिक जागरण लिखता है– महिला को किया डिजिटल अरेस्ट, पौने दो करोड़ ठगे, खुद को सीबीआई का अफसर बताकर महिला को डराया।

एक अन्य ख़बर पर केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के हवाले से हिंदुस्तान समाचार पत्र ने लिखा है– दिल्ली–दून एक्सप्रेसवे पर दो माह में फर्राटा भरेंगे वाहन।